

झारखण्ड गजट

साधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 7

राँची, बुधवार

24 फाल्गुन, 1937 (श॰)

15 मार्च, 2017 (ई॰)

विषय-सूची

ਧੂष्ठ

पृष्ठ

भाग 1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।
भाग 1-क-स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।
भाग 1-ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप॰-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।
भाग 1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।
भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि।

भाग 3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण। 147-153 **भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति

एम.एस.और की अनुमित मिल चुकी है। भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में प्रःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- पूरक "अ"

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना 3 मार्च, 2017

संख्या-2/आरोप. दुमका-119/2016 -1142 (2)/रा॰-- श्री उमाकांत तिवारी, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), तसदीक शिविर, मोहनपुर, देवघर (सम्प्रति सेवानिवृत) को इनके उक्त पदस्थापन के दौरान सरकारी जमीन का खाता विभिन्न रैयतों के नाम खोलने जबिक उन लोगों के पास वैध एवं विधिवत् दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं था, संबंधी आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के स्पष्टीकरण कंडिका (क) के तहत विभागीय अधिसूचना सं॰-1818/रा., दिनांक 13 जून, 2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

- 2. उक्त विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा दायर याचिका सं॰ W.P. (S) No.-6988/2012 उमाकांत तिवारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2013 को पारित अंतरिम आदेश में उक्त याचिका के अंतिम निष्पादन तक इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पर रोक लगा दिए जाने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को स्थिगित करते हुए सभी संबंधित मूल अभिलेख वापस कर दिया गया ।
- 3. पुनः सं॰ W.P. (S) No.-6988/2012 उमाकांत तिवारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को पारित आदेश में विभागीय अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2012 को निरस्त करते हुए आदेश प्राप्ति के 16 सप्ताह के अन्दर अनुमान्य सेवांत बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश किया गया।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री उमाकांत तिवारी, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (राजस्व), तसदीक शिविर, मोहनपुर, देवघर (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संबंधी विभागीय अधिसूचना सं०-1818/रा., दिनांक 13 जून, 2012 को निरस्त किया जाता है एवं उनके सेवानिवृत उपरांत अनुमान्य बकाया राशि के भ्गतान का आदेश दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद, सरकार के उप सचिव ।

अधिसूचना 7 मार्च, 2017

संख्या-9/आरोप -33/2015-1200/रा॰-- श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के तत्कालीन आप्त सचिव (सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलाम्) एवं डॉ॰ प्रदीप पाण्डेय, जिला आर.सी.एच. पदाधिकारी, गुमला के बीच अनुचित कार्य के बदले पैसे के लेन-देन की बातचीत की खबर दिनांक 19 जुलाई, 2015 को "दैनिक भास्कर" अखबार में प्रकाशित होने के मामले में विभागीय अधिसूचना सं॰- 553/रा., दिनांक 17 फरवरी, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

- 2. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं०- 564, दिनांक 3 फरवरी, 2017 द्वारा श्री सिंह को चेतावनी संसूचित करते हुए उनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया गया।
- 3. श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं०- 4175, दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-1060, दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया । इस प्रकार श्री सिंह दिनांक 28 अगस्त, 2015 से 13 मार्च, 2016 तक निलंबित रहे। इनकी निलंबन अविध को कर्तव्य पर बताई गई अविध के रूप में विनियमित किया जाता है एवं इस अविध में इन्हें पूर्ण वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्यालय आदेश 7 मार्च, 2017

संख्या-2/रा॰स्था॰ (मु॰) -48/13-1203 (2)/रा॰-- श्री गुलाब चंद राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, शहर अंचल, राँची सम्प्रति सेवानिवृत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका (राजस्व) को विभागीय आदेश संख्या-1272/रा॰, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139 (ख) के तहत श्री राम के पेंशन से 50% की राशि 05 (पाँच) वर्षों तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-6346/रा॰, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा पूर्व की अधिसूचना सं०-1272/रा॰, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को निरस्त करते हुए श्री गुलाब चंद राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, शहर अंचल, राँची (सम्प्रति सेवानिवृत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व) के पेंशन से से 50% की राशि 05 (पाँच) वर्षों तक कटौती के आदेश को वापस किया गया है।

उक्त आलोक में श्री गुलाब चंद राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, शहर अंचल, राँची सम्प्रति सेवानिवृत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका (राजस्व) के पेंशन से 50% की राशि 05 (पाँच) वर्षों तक कटौती के बकाया राशि के भुगतान एवं पूर्ण पेंशन के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव ।

आदेश 9 मार्च, 2017

संख्या-03/आरोप-राँची-127/05-1243 (03)-- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कानूनगो शहरी भू-हदबंदी शाखा, राँची सम्प्रति अंचल निरीक्षक, खलारी के विरूद्ध भ्रामक एवं तथ्यहीन प्रतिवेदन समर्पित करने संबंधी आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-2845, दिनांक 25 सितम्बर, 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । उक्त विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

2. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों, उनके बचाव पक्ष तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत विभाग के निर्णयानुसार श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, अंचल निरीक्षक को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना 9 मार्च, 2017

संख्या-09/आरोप- रामगढ़-84/2016-1244 (09) /रा-- श्री लाल बाबु, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के थाना काण्ड सं॰-6/16, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में दिनांक 31 अगस्त, 2016 को हिरासत में लिए जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-5480, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (2)(क) के तहत गिरफ्तारी की तिथि 31 अगस्त, 2016 से अगले आदेश तक के लिए उन्हें निलंबित किया गया था।

- 2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या- B.A. No.-9024/2016 में दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने के पश्चात श्री लालबाबू द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, पलामू में दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 को योगदान समर्पित किया गया । उक्त के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (3)(i) के तहत श्री लाल बाबू का योगदान स्वीकृत करते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है ।
- 3. श्री श्री लाल बाबू के निलंबन की अविध के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध दर्ज थाना थाना काण्ड सं०-6/16, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद, सरकार के उप सचिव ।

आदेश 9 मार्च, 2017

संख्या-09/आरोप- सरायकेला-खरसावां-101/2016-1247(09)/रा-- श्री कृष्णा सोय, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नगड़ी, राँची को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के थाना काण्ड सं॰- 60/16, दिनांक 22 अगस्त, 2016 में दिनांक 23 अगस्त, 2016 को हिरासत में लिए जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या-5058, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (2)(क) के तहत गिरफ्तारी की तिथि 23 अगस्त, 2016 से अगले आदेश तक के लिए उन्हें निलंबित किया गया था।

- 2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या- B.A. No.-9273/2016 में दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने के पश्चात श्री सोय द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, पलामू में दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 योगदान समर्पित किया गया । उक्त के आलोक में विभाग के निर्णयानुसार झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (3) (i) के तहत श्री सोय का योगदान स्वीकृत करते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त किया जाता है ।
- 3. श्री सोय के निलंबन की अविध के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध दर्ज थाना थाना काण्ड सं॰-60/16, दिनांक 22 अगस्त, 2016 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद, सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, झारखण्ड गजट (साधारण) 7--50 ।